

प्रेषक,
विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग- 02

देहरादून, दिनांक 21 जून, 2011:

विषय :- वित्तीय वर्ष 2011-12 में डेरी विकास विभाग को डेरी विकास योजना (एस0सी0एस0पी0) में आयोजनागत पक्ष की राज्य योजना में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, (वित्त) के शासनादेश संख्या-209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31-3-2011 के क्रम में एवं आपके पत्र संख्या 217-19/लेखा-प्रस्ताव आयो0 एस.सी.एस.पी./2010-11, दिनांक 02-05-2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रथम त्रैमास के व्यय हेतु डेरी विकास योजना अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ डेरी विकास विभाग को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न मदों में कुल धनराशि ₹ 6.25 लाख (₹ छः लाख पच्चीस हजार मात्र) आपके निर्वर्तन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

धनराशि (लाख ₹ में)		
क्र0सं0	मद का नाम	धनराशि
1.	यातायात अनुदान	4.30
2.	प्रबंधकीय अनुदान	1.95
	कुल योग :-	6.25

(कुल ₹ छः लाख पच्चीस हजार मात्र)

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि की फॉट निदेशक, डेरी द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित जिला स्तर के अधिकारियों, दुग्ध संघों एवं शासन को अवगत कराया जायेगा।
2. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय, साथ ही इस धनराशि का एक मुश्त आहरण न किया जाय।
3. सभी कार्यों का जनपदवार वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण भी आपके द्वारा तत्काल कर दिया जाय तथा फील्ड स्तर पर भी निर्धारित किये गये लक्ष्यों की सूचना उपलब्ध करा दी जाय।
4. उक्त धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत ही किया जाय।
5. स्वीकृति धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम 75 प्रतिशत से अधिक पूर्ण कार्यों के लिये किया जाये।
6. अवमुक्त की जा रही धनराशि अनुसूचित जाति के सदस्य संख्या के प्रतिशत के अन्तर्गत किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद से किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

1

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग- 02

देहरादून, दिनांक 21 जून, 2011:

विषय :- वित्तीय वर्ष 2011-12 में डेरी विकास विभाग को डेरी विकास योजना (टी0एस0पी0) में आयोजनागत पक्ष की राज्य योजना में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, (वित्त) के शासनादेश संख्या-209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31-3-2011 के क्रम में एवं आपके पत्र संख्या 220-22/लेखा-प्रस्ताव आयो0 टी.एस.पी. /2011-12, दिनांक 02-05-2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रथम त्रैमास के व्यय हेतु डेरी विकास योजना अनुसूचित जन जाति के कल्याणार्थ डेरी विकास विभाग को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न मदों में कुल धनराशि ₹ 1.25 लाख (₹ एक लाख पच्चीस हजार मात्र) आपके निर्वर्तन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

धनराशि (लाख ₹ में)

क्र0सं0	मद का नाम	धनराशि
1.	यातायात अनुदान	1.00
2.	प्रबंधकीय अनुदान	0.25
	कुल योग :-	1.25

(कुल ₹ एक लाख पच्चीस हजार मात्र)

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि की फॉट निदेशक, डेरी द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित जिला स्तर के अधिकारियों, दुग्ध संघों एवं शासन को अवगत कराया जायेगा।
2. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय, साथ ही इस धनराशि का एक मुश्त आहरण न किया जाय।
3. सभी कार्यों का जनपदवार वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण भी आपके द्वारा तत्काल कर दिया जाय तथा फील्ड स्तर पर भी निर्धारित किये गये लक्ष्यों की सूचना उपलब्ध करा दी जाय।
4. उक्त धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत ही किया जाय।
5. स्वीकृति धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम 75 प्रतिशत से अधिक पूर्ण कार्यों के लिये किया जाये।
6. अवमुक्त की जा रही धनराशि अनुसूचित जनजाति के सदस्य संख्या के प्रतिशत के अन्तर्गत किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद से किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।